माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत याचिका अस्वीकार की; जेएनपीए वाढवण पत्तन के नियोजित विकास कार्य को आगे बढ़ाएगा

मुंबई, 13 अक्टूबर 2025: मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) महाराष्ट्र राज्य के पालघर ज़िले के दहानू तालुका में वाढवण पत्तन का विकास कर रहा है। यह परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी पत्तन अवसंरचना पहलों में से एक है। कुछ स्थानीय संगठनों ने इस परियोजना को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इन संगठनों ने वाढवण, दहानू तालुका में मेजर पोर्ट की स्थापना से संबंधित किसी भी कार्य को रोकने के लिए अंतरिम राहत के रूप में स्थगन आदेश की मांग की थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28.02.2025 के आदेश के तहत, जेएनपीए द्वारा प्रस्तुत वाढवण पत्तन परियोजना के विकास कार्यक्रम को अभिलेख में लेते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत की प्रार्थना को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही और अन्य संबंधित प्रक्रियाएँ लंबित याचिकाओं में आगामी आदेशों के अधीन रहेंगी।

आज की तारीख तक, वाढवण पत्तन के विकास कार्य पर कोई रोक नहीं है, और जेएनपीए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए अनुमोदित कार्यक्रम के अनुरूप परियोजना को आगे बढ़ा रहा है।

विकास के इस चरण पर बोलते हुए, श्री उन्मेष शरद वाघ, भा. रा. से., अध्यक्ष – जेएनपीए तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाढवण पत्तन प्रोजेक्ट लिमिटेड ने कहा,

“माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भारत के समुद्री दृष्टिकोण और उचित प्रक्रिया की अखंडता में विश्वास की पुष्टि करता है। वाढवण पत्तन केवल एक अवसंरचनात्मक परियोजना नहीं है, बल्कि यह प्रगति का प्रतीक है — जो देश के पश्चिमी तट को वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने जा रहा है। हमारा प्रयास संवेदनशीलता और संतुलन पर आधारित है — ताकि विकास समुदाय की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर आगे बढ़े। हम स्थानीय निवासियों के कल्याण के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, और ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ विकास और सामंजस्य साथ-साथ पनपें, तथा प्रगति के लाभ सर्वसमावेशी और संपोषणीय रूप से साझा हों।”

वाढवण पत्तन परियोजना का उद्देश्य पत्तन क्षमता में वृद्धि करके, क्षेत्रीय विकास को गति देकर तथा वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करके भारत के समुद्री परिदृश्य को पुनः परिभाषित करना है।

वीपीपीएल के बारे में:

वढवाण पत्तन प्राइवेट लिमिटेड (वीपीपीएल) भारत का 13वां प्रमुख पत्तन है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) के बीच गठित एक स्पेशल परपज़ वेहिकल (एसपीवी) के रूप में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के पालघर ज़िले के दहानू के समीप रणनीतिक रूप से स्थित यह पत्तन वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पत्तनों में स्थान प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। इस पत्तन की आधारशिला 30 अगस्त 2024 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी।

संपोषणीय विकास के प्रति प्रतिबद्ध, वीपीपीएल को प्रारंभ से ही 100% हरित (ग्रीन) पत्तन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम रहे। 24 मिलियन टीईयू

(TEUs) की संभाल क्षमता के साथ यह पत्तन व्यापारिक दक्षता में वृद्धि करेगा, आर्थिक विकास को गति देगा और क्षेत्रीय प्रगति में योगदान देगा। वढवाण पत्तन स्किलिंग प्रोग्रा* जैसी पहलों के माध्यम से वीपीपीएल स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर जाएँ:

वीपीपीएल वेबसइट- https://vadhvanport.in/

X- VadhvanPort

फेसबुक - Vadhvan Port Project Ltd

इंस्टाग्राम -vadhvanport

लिंक्डइन -Vadhvan Port Project Ltd

मीडिया पूछताछ के लिए संपर्क करें:

अंबिका सिंह,

उप महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट संचार और प्रशिक्षण), वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड।

मोबाइल: +919920372677

ई-मेल: ambikasingh@jnport.gov.in

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम मदत याचिका फेटाळली; जेएनपीए वाढवण बंदराच्या नियोजित विकासासाठी पुढील कार्यवाही करणार

मुंबई, १३ ऑक्टोबर २०२५: मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनुसार, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर विकसित करत आहे. भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी बंदर पायाभूत सुविधांपैकी एक असलेल्या या प्रकल्पाला काही स्थानिक संघटनांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या संघटनांनी डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे प्रमुख बंदराच्या स्थापनेशी संबंधित कोणत्याही कामाला स्थगिती देण्याच्या आदेशांच्या स्वरूपात अंतरिम दिलासा मागितला होता.

२८.०२.२०२५ च्या आदेशानुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, जेएनपीएने सादर केलेल्या वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या विकास वेळापत्रकाची नोंद घेत, याचिकाकर्त्यांनी मागितलेली अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती फेटाळून लावली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की अधिग्रहण कार्यवाही आणि इतर संबंधित पावले प्रलंबित याचिकांमध्ये पुढील आदेशांच्या अधीन राहतील.

सद्यस्थितीत वाढवण बंदराच्या विकासकामांवर कोणतीही स्थगिती नाही, आणि जेएनपीए सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या मंजूर आराखड्यानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी पुढे नेत आहे.

या घडामोडीवर भाष्य करताना जेएनपीएचे अध्यक्ष आणि वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (व्हीपीपीएल) चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. उन्मेष शरद वाघ, भा. रा. से ., म्हणाले, "सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा भारताच्या सागरी दृष्टिकोनावर आणि विधिसंगत प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. वाढवण बंदर हा केवळ पायाभूत प्रकल्प नाही — तो प्रगतीचे प्रतीक आहे, जो भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याला जागतिक व्यापाराच्या केंद्रांशी जोडणार आहे. आमचे प्रयत्न सदैव संवेदनशीलता आणि संतुलन यांवर आधारित असतात — जेणेकरून विकास हा स्थानिक समुदायाच्या हानीवर नव्हे तर त्यांच्या सहकार्याने साधला जाईल. स्थानिक नागरिकांच्या कल्याणासाठी आमची बांधिलकी अविचल आहे. आम्ही असे एक परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, जिथे विकास आणि सुसंवाद यांचा समन्वय साधला जाईल आणि प्रगतीचे लाभ सर्वसमावेशक आणि शाश्वत पद्धतीने सामायिक केले जातील."

वाढवण बंदर प्रकल्पाचा उद्देश भारताच्या सागरी क्षेत्राला नव्या रूपात परिभाषित करण्याचा आहे. या प्रकल्पाद्वारे बंदर क्षमतेत वाढ होईल, प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल आणि भारताचे स्थान जागतिक लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून अधिक दृढ होईल.

व्हीपीपीएल बद्दल:

वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (VPPL) हे देशाचे १३वे मोठे बंदर असून, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (JNPA) आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (MMB) यांच्या संयुक्त भागीदारीत स्थापन करण्यात आलेले एक विशेष उददिष्ट असलेले कंपनी रूपातील उपक्रम आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळ वसलेले हे बंदर जागतिक स्तरावर आघाडीच्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवण्यास सक्षम आहे. ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या बंदराच्या भूमिपूजनाचा ऐतिहासिक क्षण घडला.

निसर्गपूरकतेला प्राधान्य देत, वाढवण बंदर हे शंभर टक्के हरित तत्त्वावर आधारित असणार आहे, जे पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम करत अधिक कार्यक्षमतेने काम करेल. २४ दशलक्ष टीईयू (TEU) माल हाताळण्याची क्षमता असलेले हे बंदर देशाच्या व्यापार कार्यक्षमतेला गती देणार आहे. या माध्यमातून आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल आणि परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल. वाढवण पोर्ट कौशल्य कार्यक्रमांसारख्या उपक्रमांद्वारे स्थानिक समुदाय सशक्त करण्यावर वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड विशेष भर देत आहे.

अधिक जाणून घेण्यासाठी आमच्या संकेतस्थळावर आणि सोशल मीडियाला भेट द्या:

व्हीपीपीएल संकेतस्थळ - https://vadhvanport.in/

फेसबुक - Vadhvan Port Project Ltd

X- VadhvanPort

इंस्टाग्राम - vadhvanport

लिंक्डइन - Vadhvan Port Project Ltd

माध्यम प्रतिनिधींनी अधिक माहितीसाठी संपर्क साधावा:

अंबिका सिंग,
उपमहाव्यवस्थापक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन व प्रशिक्षण),
वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड
मोबाईल क्र. : +919920372677
ईमेल: ambikasingh@inport.gov.in

Hon’ble Supreme Court Declines Interim Relief Plea; JNPA to Proceed with Scheduled Development of Vadhvan Port

Mumbai, October 13, 2025: Pursuant to the Cabinet approval, Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) is developing the Vadhvan Port at Taluka Dahanu, District Palghar, Maharashtra. The project, one of India’s most ambitious port infrastructure initiatives, had been challenged by certain local associations before the Hon’ble Supreme Court of India. These associations had sought interim relief in the form of restraining orders to halt any work relating to the establishment of a Major Port at Vadhvan, Dahanu Taluka.

Vide order dated **28.02.2025**, the Hon’ble Supreme Court, after taking on record the development schedule of the Vadhvan Port Project submitted by JNPA, **dismissed the prayer for interim relief** sought by the petitioners. The Court observed that the acquisition proceedings and other related steps would remain subject to further orders in the pending petitions.

As of date, **there is no stay on the development work of Vadhvan Port**, and JNPA continues to pursue the project in line with the approved schedule placed before the Hon’ble Supreme Court.

Speaking on the development, **Shri Unmesh Sharad Wagh, IRS, Chairperson, JNPA and CMD, Vadhvan Port Project Ltd. (VPPL)**, stated, *“The Hon’ble Supreme Court’s order reaffirms faith in India’s maritime vision and the integrity of due process. Vadhvan Port is not merely an infrastructural undertaking—it is an emblem of progress, poised to connect the nation’s western coast with the world’s trade arteries. As we move ahead, our endeavour remains guided by sensitivity and balance—ensuring that development does not come at the expense of community, but rather, in concert with it. We remain deeply committed to the well-being of local residents, striving to create an ecosystem where growth and harmony coexist, and where the benefits of progress are shared inclusively and sustainably.”*

The Vadhvan Port Project is envisioned to redefine India's maritime landscape by enhancing port capacity, catalysing regional development, and strengthening the nation's position as a global logistics hub.

About VPPL:

Vadhvan Port Private Limited (VPPL) is the 13th major port of India, a special purpose vehicle (SPV) formed between Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) and the Maharashtra Maritime Board (MMB). Strategically located in Palghar district, near Dahanu, Maharashtra, VPPL is poised to be among the top 10 ports globally. The foundation stone for the port was laid on August 30th, 2024, by the Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.

Committed to sustainability, VPPL will be 100% green from inception, ensuring minimal environmental impact. The port is set to enhance trade efficiency with the capacity to handle 24 million TEUs, stimulate economic growth, and contribute to regional development. Through initiatives like the Vadhvan Port Skilling Program, VPPL focuses on empowering local communities.

Visit our website and social media to learn more:

VPPL Website: https://vadhvanport.in/

X - VadhvanPort

Facebook - Vadhvan Port Project Ltd

Instagram - vadhvanport

LinkedIn - Vadhvan Port Project Ltd

For Media Queries, Contact:

Ambika Singh,
DGM(Corporate Communications & Training), Vadhvan Port Project Ltd.

Mob: +919920372677
E-mail: ambikasingh@jnport.gov.in